

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1,

देहरादून: दिनांक 66 अप्रैल, 2015

विषय:- स्थान सोनप्रयाग में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त/वासआऊट हुए होटल, लॉज, ढाबे, अस्थाई छप्परों/दुकानों के प्रभावितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वर्ष 2013 में जून माह में घटित प्राकृतिक आपदा से स्थान सोनप्रयाग के स्थानीय व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान (पक्के होटल, लॉज, दुकानें, कच्चे ढाबे एवं छप्पर आदि) जो राज्य की गैर जमींदारी विनाश भूमि रकवा 8-9 नाली (1600 वर्ग मी०) पर बने थे तथा उक्त भूमि पर अवैध रूप से काबिज थे के वासआऊट हो जाने के दृष्टिगत प्रभावितों के पुनर्वास व मुआवजे तथा वर्तमान में मौके पर आंशिक अथवा गंभीर क्षति की अवस्था में खड़े 15 व्यावसायिक भवनों को प्रस्तावित मल्टी स्टोरी पार्किंग एवं शापिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु तोड़े जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

- 1) मौके पर खड़े 15 व्यावसायिक भवनों को लो०नि०वि० की वर्तमान शेड्यूल ऑफ रेट (SOR) के आधार पर कुल ₹ 1,97,70,000.00 (एक करोड़ सत्तानवे लाख सत्तर हजार मात्र) मूल्यांकन जिला स्तर पर आंकलित हुआ है। पूर्व में उक्त भवनों को हुई क्षति के अनुरूप जिल प्रशासन द्वारा सम्बन्धित भवन स्वामियों को ₹ 21,53,193.00 (इक्कीस लाख तिरेपन हजार एक सौ तिरानवे मात्र) का भुगतान राहत राशि के रूप में किया जा चुका है।
- 2) पूर्व में किये गये उपरोक्त भुगतान के समायोजन उपरान्त इन 15 भवनों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण हेतु सरकार द्वारा सम्बन्धित भवन स्वामियों को कुल ₹ 1,76,16,807.00 (एक करोड़ छिहत्तर लाख सोलह हजार आठ सौ सात मात्र) की शेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 3) 40 आपदा प्रभावित व्यक्ति/परिवारों को स्थान सोनप्रयाग में प्रस्तावित शापिंग कॉम्प्लेक्स में निःशुल्क पक्की दुकाने (20X30 फीट तथा 10X20 फीट) आवंटित की जायेंगी। 35 प्रभावित व्यक्ति/परिवारों जिनके आपदा से पूर्व अस्थाई छप्पर/दुकानें स्थापित थी, को पक्के Kiosk निर्माण कर आवंटित किया जायेगा।
- 4) मल्टी स्टोरी पार्किंग व शापिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के उपरान्त स्थान सोनप्रयाग में शेष बचे भूखण्ड में सम्बन्धित आपदा प्रभावितों को उनके पूर्व में कब्जे की भूमि के रकवे के अनुरूप भूमिधरी अधिकार दिया जायेगा।
- 5) भवन ध्वस्तीकरण व पुनर्वास सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व प्रभावित व्यक्ति एवं जिलाधिकारी/पुनर्वास, विस्थापन आयुक्त के मध्य शपथ पत्र में उपरोक्त शर्तों पर सहमति अभिलिखित की जायेगी।

-2-

2- उपरोक्त राहत व्यवसायियों को श्री केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य की जा रही है। अतः इसे अन्यत्र नजीर के रूप में नहीं लिया जायेगा।

3- यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-02NP/XXVII(5)/2015-16, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या-920 () /XVIII-(2)/2015-15(18)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ 5- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- अधिशासी निदेशक, डी०एम०एम०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव